ध्रुबज्योति भट्टाचार्य: धन्यवाद, महोदया। अब मैं राजदूत अनिल त्रिगुणायत से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना वक्तव्य दें और कार्यवाही का संचालन करें।

अनिल त्रिगुणायत: धन्यवाद। आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। पाकिस्तान के मुद्दे पर ऐसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की संगति का होना सौभाग्य की बात है। हम सभी उनके योगदानों के बारे में पढ़ते और सुनते रहे हैं। लेकिन हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा कि हम पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। अतीत में पाकिस्तान ने हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयास किया, हम इससे बच सकते थे। सौभाग्य से, हम अब ऐसा ही कर रहे हैं।

भारत ने हमेशा से माना है कि आर्थिक रूप से सशक्त पाकिस्तान हमारे लिए अच्छा है, जो हमारी 'पड़ोसी पहले' वाली नीति का एक हिस्सा है, यह पाकिस्तान पर भी समान रूप से लागू होता है लेकिन इसके बदले पाकिस्तान ने भी भारत के प्रति एक नीति का पालन किया है, आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के हथियार के रूप में वर्षों से इस्तेमाल कर रहा है। आज, जैसा कि *भस्मासुर* की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, टीटीपी (TTP) के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद की जा रही है, कई आतंकी हमले हुए हैं। सुरक्षा बल जो इस बात पर गर्व करते थे कि वे ही देश की असली ताकत हैं, तथाकथित लोकतांत्रिक तरीके से जिसे भी चुना जाता है, उसके रहनुमा बन जाते हैं, वे सुरक्षा बल ही पाकिस्तानी आवाम की रक्षा करने में असफल रहे हैं। साल 2024 खुद को हुए नुकसान, हमलों की संख्या के लिहाज से सबसे बुरा वर्ष रहा, हाल ही में उनका अपने दूसरे पड़ोसियों, पश्चिमी देश के पड़ोसियों और अफ़गानिस्तान के साथ भी विवाद हुआ।

साल 2025 शुरु हो चुका है, बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्यों एवं इरान के साथ विवाद के बीच पाकिस्तान का फोकस भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों पर बना हुआ है। इसलिए हमारा ऐसी गतिविधियों पर नज़र रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मामले में चीन एक और प्रमुख कारक है। इसलिए आज का पाकिस्तान, जैसा कि हम इसे देखते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, जैसा कि कार्यवाहक महानिदेशक ने

इसे बहुत ही शानदार तरीके से परिभाषित किया है, सत्ता का निरंतर संघर्ष है, जो दुनिया के इस हिस्से में बहुत स्वाभाविक है।

मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां आम बात है। राजनेताओं में जन कल्याण के प्रति किसी प्रकार की भी वास्तविक प्रतिबद्धता में दिलचस्पी दिखाई नहीं देती। इसलिए लोग खुलेआम चर्चा करते हैं कि अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं चल रही है। आज, कुछ संकेतक बताते हैं और मुझे यकीन है कि पैनल के सदस्य भी इन मुद्दों पर अपनी बात कहेंगे। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है और मुझे भरोसा है कि इस पैनल के सम्मानित सदस्य इस पर विचार- विमर्श करेंगे कि हम विभिन्न राजनीतिक दलों की घरेलू समस्याओं के बारे में बात करेगें, इमरान खान का क्या होगा, पीटीआई का क्या होगा, इन सब में ट्रंप की भूमिका क्या होगी, ये सभी बातें शायद चर्चा का हिस्सा बनें।

लेकिन मेरा मानना है कि भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए हमें यह भी देखना होगा कि क्या पाकिस्तान की सेना और उसके खुफिया संगठन उसी रास्ते पर चलते रहेंगे जिस पर वे अब तक चलते आए हैं। या हम किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने कई प्रकार की चुनौतियां हैं और हर कोई उन्हें साफ- साफ देख सकता है, समझ सकता है कि कितनी मुश्किलें आने वाली हैं। इसलिए हमें इन पर भी ग़ौर करना होगा।

पाकिस्तान में 8 फरवरी को नई सरकार सत्ता में आई, चुनाव हुए, पीटीआई पार्टी को अपने दम पर चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए उन्होंने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीतीं लेकिन वे सत्ता का हिस्सा नहीं थे। बाकी दो पार्टियों ने कुछ और दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई। घरेलू स्तर पर उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए हमें इससे निपटना होगा क्योंकि विश्व के हमारे हिस्से में कहीं भी अशांति हो तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है और इस क्षेत्र में सबसे बड़े देश होने के नाते इस मामले में हमें हमेशा बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पिछले चुनावों में एक और बात यह हुई कि पाकिस्तान के चुनावों में युवाओं की भागीदारी बढ़ी, पिछले चुनाव में इनकी भागीदारी करीब 33% की थी। इस बार, चुनावों में 44% युवाओं ने हिस्सा लिया था, पाकिस्तान की निराशापूर्ण स्थिति में यह आंकड़ा बेहद दिलचस्प है।

लेकिन विदेश नीति के मामले में, हमें यह देखना होगा कि कैसे और आप सभी इसका अर्थ समझ रहे हैं क्योंकि आप सभी ने इसके बारे में सोचा होगा कि पाकिस्तान के पास एक प्रकार का उपद्रव मूल्य हुआ करता था, या शायद अभी भी है, जिसका इस्तेमाल वह सभी महाशक्तियों चाहे वह अमेरिका हो, चीन हो या रूस, से, लाभ उठाने के लिए करता है, और इन सभी महाशक्तियों ने किसी- न- किसी रूप में उसे लाभ पहुँचाया भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत हमेशा से पाकिस्तान में स्थिरता का पक्षधर रहा है। हम कभी भी पाकिस्तान को अस्थिर नहीं करना चाहते थे। यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है।

इसलिए, मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे केवल पांच मिनट ही मिले हैं अपनी बात रखने को, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे पास प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का एक ऐसा पैनल है जो इस विषय में बहुत कुछ जानते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान में काम नहीं किया है लेकिन मैं एक भूतपूर्व राजनयिक हूँ और इस वज़ह से आपका प्रमुख कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने दोस्तों की गतिविधियों पर नज़र रखें और उनकी गलत सोच का मुकाबला करने का प्रयास करें।

तो अब मैं श्री तिलक देवाशेर से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री देवाशेर एक एक लेखक हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं और पाकिस्तान के मुद्दों के विशेषज्ञ भी। मुझे लगता है हर एक विशेषज्ञ को अपनी बात रखने के लिए दस मिनट मिलेंगे।

तिलक देवाशेर: धन्यवाद। आपका बहुत- बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, पैनल के साथी सदस्यों, विशिष्ट अतिथिगण। जैसा कि परिचय में कहा गया है, 2025 में प्रवेश करते समय पाकिस्तान को कई समस्याओं और संकटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ऐसा शायद ही कोई समय रहा हो जब पाकिस्तान को संकटों का सामना न करना पड़ा हो। यह हमेशा ही गंभीर स्थिति में होता है- एक *'नाज़ुक मोड़'*। अब मैं संपादकीय से उद्धरण देता हूँ जो बहुत दिलचस्प है। "अब लगभग एक दशक से, राजनीतिक असीमित लालच और सीमित क्षमता से अभिशप्त लोगों के लिए खेल का सुरक्षित मैदान रहा है। हर साल संकट का साल रहा है, और हर मौसम, साज़िश का मौसम रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे राजनीतिक जीवन में एकमात्र स्थिर कारक निरंतर अस्थिरता रही है।"

अब ये शब्द शायद कल लिखे जाएँ लेकिन वास्तव में ये पाकिस्तान टाइम्स के संपादकीय में पाकिस्तान के गठन के 11वीं वर्षगांठ पर 1958 में लिखे गए थे। आप समय में थोड़ा आगे बढ़ेंगें और हाल के संपादकीय से इसकी तुलना करेंगें तो, मैं कहना चाहूँगा "आज, पाकिस्तान फिर से एक चौराहे पर खड़ा है, जहाँ राजनेता एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और जहाँ मुल्क की आवाम को उनके हाल पर रहने या फिर मुल्क छोड़ कर चले जाने के लिए छोड़ दिया दया है। व्यवस्था यानी सिस्टम में भरोसा वापस लाने का एकमात्र तरीका है अपनी गलतियों को स्वीकार करना, माफ़ी मांगना, सुधार करना और फिर संकट को हल करने के लिए बातचीत करना। अन्यथा, व्यवस्था बहुत तेज़ी से, भरभरा कर ढह जाएगी"। यह अप्रैल 2023 से है। आप कोई सा भी उठा कर देख लें, सभी में एक जैसी भावना ही व्यक्त मिलेगी।

मुझे 1958 और 2023 की स्थितियों के बीच की समानता ने चौंका दिया, जो आश्चर्यजनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि समय गुज़र गया लेकिन पाकिस्तान वहीं ठहरा हुआ है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान समय- समय पर संकट में रहा है और अब उसका संकट बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे एक प्रकार की आत्मतुष्टि की धारणा पैदा हो गई है, खासतौर पर भारत में, चूंकि पाकिस्तान पहले के संकटों से उबर चुका है इसलिए वह वर्तमान संकट से भी उबर जाएगा। लेकिन विश्लेषक के तौर पर मुझे लगता है कि

आज की स्थिति बीते 70 साल की स्थिति से शायद अलग है, और हमें इस अंतर के विभिन्न तत्वों पर विचार करने की जरूरत है। पाकिस्तान अतीत की तुलना में कहीं अधिक गंभीर स्थिति से क्यों गुज़र रहा है?

शायद बीते 70 वर्षों में कभी भी समय और स्थान पर इतनी गंभीर समस्याएं एक साथ नहीं आई हैं, जितनी कि आज हैं। गंभीर राजनीतिक संकट की स्थिति है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और सुरक्षा की स्थिति बद- से- बदतर होती जा रही है।

अब, ये समस्याएं क्यों दिखाई देने लगीं हैं? और धरातल पर, पाकिस्तान एक बड़े संकट से जूझ रहा है जो सिर उठाने वाला है। अपनी पहली किताब, *पाकिस्तानः कोर्टिंग द एबिस* में मैंने एक बुनियादी सवाल पूछा था। "क्या पाकिस्तान पर शासन करना संभव नहीं है या इसके नेता पाकिस्तान पर शासन करने में असमर्थ हैं"? पाकिस्तान आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में भी इस एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। मेरे तर्क का पहला बिंदु डब्ल्यूईईपी (WEEP) कारक था। मैंने जल (वाटर), शिक्षा (एजुकेशन), अर्थव्यवस्था (इकॉनमी) और जनसंख्या (पॉपुलेशन) के लिए ये संक्षिप्त नाम तैयार किया था। ये सुरक्षा संबंधी दीर्घकालिक, गैर- परंपरागत संकट हैं जो किसी भी देश की अंदरूनी संरचना को खोखला बना देते हैं। इनके खराब होने में दशकों लग जाते हैं और ठीक होने में इससे भी अधिक समय लगता है।

मैंने एक दशक पहले ही बताया था कि पाकिस्तान इन सभी क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति से जूझ रहा है और आज उसे आपदा प्रबंधन मोड में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होने का कोई संकेत नहीं था। मैंने एक सवाल पूछा था जो किताब के प्रकाशन वर्ष, यानि 2016 में महत्वपूर्ण था, वही सवाल आज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान कई संकटों का सामना कर रहा है।

इस स्थिति में दूसरा नया घटक इमरान खान का व्यक्तित्व और उनकी निस्संदेह लोकप्रियता है। सत्ता प्रतिष्ठान की उपज, इमरान खान ने गुंडागर्दी की और अपने समर्थकों को पाकिस्तान में अभूतपूर्व तरीके से चुनौती दी। उनकी अपार लोकप्रियता के कारण सेना, भूतपूर्व सैनिकों, न्यायपालिका, माफिया भी अब तक उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने जवाबदेही के नारों- *तब्दीली, नया पाकिस्तान और भ्रष्टाचार मुक्त रियासत- ए- मदीना,* से शहरी मध्यम वर्ग और युवाओं को सम्मोहित कर लिया है।

लोग जिस दलदल में फंसे हैं, उसमें इमरान खान के दिखाए सपने अफ़ीम की तरह काम कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि जेल से भी वे सत्ता प्रतिष्ठान के लिए खतरा हैं और बहुत कम समय में स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। तीसरा तत्व है जनसांख्यिकी, जिसका उल्लेख अध्यक्ष महोदय ने किया था और राजनीति में युवाओं की अधिक भागीदारी, जिसने खुद को इमरान खान के पक्ष में दिखाया है। इसके स्पष्ट चुनावी निहितार्थ हैं, साथ ही गली- मुहल्लों में भी इसके निहितार्थ हैं। 47% से अधिक मतदाता, या लगभग 58 मिलियन (5 करोड़ 80 लाख), 18 से 35 वर्ष की उम्र के युवा मतदाता हैं। युवाओं की सक्रियता, जिसे मतपेटी में वोट के रूप में देखा जाए, सारे समीकरण बदलने वाली होगी, लेकिन गली- मोहल्लों के लिए ये बड़ा समीकरण बदलने वाला साबित होगा क्योंकि वे सरकार को पंगु बना सकते हैं।

चौथा, राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाला एक और कारक है सोशल मीडिया। संस्थान और राजनीतिक दल जिन परंपरागत तरीकों के जरिए जो भावनात्मक पृष्ठभूमि तैयार करते थे, वे अब काम नहीं करते। हालांकि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अक्सर सरकारी नियंत्रण में होते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर रोक लगाना मुश्किल है। यह एक ऐसा जन- आंदोलनकारी माध्यम है जो जनता की भावनाओं को भुनाता है और उन्हें उकसाता है और पृष्ठभूमि को आकार देता है। सोशल मीडिया पर पृष्ठभूमि तैयार करने के मामले में पीटीआई (PTI) दूसरी पार्टियों के मुकाबले बहुत आगे है।

आखिर में, अतीत में, पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाता था, जिससे उसे कमाई होती थी। आज के वैश्विक माहौल में पाकिस्तान संकट में है, अस्थिर है और उस पर भू- राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है। इनमें से कुछ हैं अमेरिका- चीन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा, यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्धरत प्रमुख देशों का फोकस और डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के कारण पैदा हुई अनिश्चितता की स्थिति। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान ने एक अग्रणी देश के रूप में अपनी उपयोगिता खो दी है।

हाल ही में, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए हैं। भारत के साथ संबंध ठंडे पड़ गए हैं जबकि पुराने जमाने का मित्र चीन ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा पर अप्रत्याशित रूप से सार्वजनिक चिंता व्यक्त कर दी है। घरेलू स्तर पर, टीटीपी (TTP) और बीएलए (BLA) के हिंसक हमले बहुत बढ़ गए हैं और सेना भी इन संगठनों से निपटने में अनिच्छुक या असमर्थ हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, बीते एक साल में पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति बहुत खराब हुई है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के अनुसार, देश में 2024 में पिछले साल की तुलना में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में 70% का इज़ाफा हुआ है। ये इजाफा न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि 2024 में दर्ज किए गए सभी हमलों में से लगभग 60% हमले सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित कर्मचारियों, वाहनों, काफिलों और सुविधाओं पर किए, यानि, कठिन लक्ष्य को पूरा किया। यह दो प्रमुख समूहों, टीटीपी (TTP) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की ताकत बढ़ रही है, को बताता है।

हिंसा में वृद्धि का एक और कारण यह है कि इन समूहों के पास अब अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा छोड़े गए अत्याधुनिक हथियार हैं। इसके अलावा, देश, मुख्य रूप से सेना, प्रभावी राजनीतिक और सामरिक रणनीतियों की परिकल्पना करने और उन्हें लागू करने में असफल रही है। यह असमर्थता मुख्य रूप से इमरान खान के मामले में उलझे रहने के कारण है। मेरे विचार से, सेना नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रभावी राजनीति तैयार करना और दूरदर्शिता एवं क्षमता प्रदर्शित

करना है। इससे यह सवाल उठता है कि सेना ऐसा करने में असमर्थ क्यों रही है? और क्या इससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान की सेना वहां के आवाम और देश पर अपनी पकड़ खो सकती है?

भुजबल के मामले में सेना, अगर बहुत मजबूत नहीं है तो उतनी ही मजबूत है जितनी हमेशा से रही है। लेकिन सेना के वर्चस्व के लिए सिर्फ भुजबल ही उत्तरदायी नहीं है। जैसा कि मेज़र जनरल शेर अली खान पटौदी ने 1969 में जनरल याह्या खान से कहा था कि "सेना के शासन करने की क्षमता इस बात में निहित है कि लोग इसे एक काल्पनिक इकाई, जादुई शक्ति के रूप में देखते हैं जो जरूरत के समय, जब कोई उम्मीद नहीं बचेगी, तब उनकी मदद करेगी। सेना पाकिस्तान और उसकी खुशहाली की अंतिम गारंटी थी। यह सेना के प्रभुत्व का दार्शनिक आधार रहा है।" सेना की छवि को एक काल्पनिक इकाई, एक जादुई शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने की इसी धारणा को इमरान खान ने- जेल से बाहर रहने के दौरान सेना पर लगाए गए उनके आरोपों, विशेष रूप से विदेश में बैठे समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए गए निंदनीय अभियानों, और 9 मई को सेना के ठिकानों पर किए गए हमलों के जरिए गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है।

इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि मौजूदा परिस्थिति में सेना राजनीति पर हावी रहेगी, विशेषरूप से अपने हितों के मुख्य मामलों में। लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान की बातों को जबरदस्ती थोपने की शक्ति चाहे वह मार्शल लॉ के माध्यम से हो या हाइब्रिड शासन के माध्यम से, अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने वैधता और करिश्मा खो दिया है। कुछ समूह और राजनीतिक दलों को लगता है कि वे सेना की ताकत का विरोध कर सकते हैं लेकिन सेना खुद नहीं मानती कि उनकी ताकत खत्म हो गई है। इसलिए टकराव और अस्थिरता अपरिहार्य हैं।

आखिर में, अपनी पुस्तक में मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर- पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी चुनौतियाँ उसके नेताओं की क्षमताओं और योग्यताओं से परे है। वर्तमान नेतृत्व के पास ऐसा

करने के लिए न तो दूरदृष्टि है और न ही क्षमता। पाकिस्तान के अयोग्य नागरिक नेतृत्व और अयोग्य सैन्य नेतृत्व के संयोजन के परिणामों की कल्पना आसानी से की जा सकती है। आप सभी का बहुत- बहुत धन्यवाद।

अनिल त्रिगुणायत: बहुत- बहुत धन्यवाद। आपने कुछ बेहतरीन बातें कही हैं और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग उनकी किताब भी पढ़ना चाहेंगे, जो कि बेस्टसेलर में से एक है। किताब उन सभी जटिल मुद्दों के बारे में बताती है जिनका ज़िक्र श्री देवाशेर ने बहुत ही सहजता के साथ किया था। इन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कुछ बिंदुओं को उठाया यानि पाकिस्तान अभी भी टाइम मशीन में फंसा हुआ है। इसलिए इसने अपना रवैया नहीं बदला है और क्या यह पहले की तरह ठीक हो पाएगा और आशा करें कि यह ठीक हो जाए। फिर कमज़ोर कारक भी बहुत दिलचस्प हैं और मुझे लगता है कि वे इस बात का अच्छा संकेत देते हैं कि यह कैसे होता है। यह तथ्य कि सेना आवाम के बीच अपनी चमक खो रही है, कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम शायद उनसे पूछेंगे कि क्या सेना थोड़ी ज्यादा सख्त हो जाएगी या वह बेहतर सार्वजनिक कूटनीति मंच के माध्यम से स्थिति से निपटेगी, लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेगी और सरकार को काम करने दिया जाएगा। इसलिए हमें देखना होगा कि यह आखिरकार कैसे होता है।

और आखिरी बात जो आपने बताई वह सच है कि चुनौतियाँ क्षमताओं, योग्यताओं से कहीं ज्यादा बड़ी हैं और मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूँगा कि इसे करने का इरादा भी है। आपका बहुत- बहुत धन्यवाद। अब मैं ज़ामिया मिलिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पाकिस्तान के मुद्दों के जाने- माने टिप्पणीकार एवं लेखक अजय दर्शन बेहरा से अनुरोध करूँगा कि वे अपनी बात रखें।

अजय दर्शन बेहरा: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय और आमंत्रण के लिए महानिदेशक महोदय को धन्यवाद। पाकिस्तान में जो समस्या है, जो संकट हम देख रहे हैं, श्री देवाशेर जी ने देश में मौजूद कई संकटों को हमारे समक्ष रखा। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। एक राजनीतिक

विज्ञानी होने के नाते मैं, यह समझना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किस दिशा में बढ़ रहा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम यह समझ सकें कि पाकिस्तान वर्तमान में किन समस्याओं से जूझ रहा है?

पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को समझने की कोशिश की जा रही है। यह उससे बहुत अलग है जिसके बारे में हम जानते हैं। मुख्य रूप से सेना के कारण, जो व्यवस्था को हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल बना देती है। जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के शासन में सेना की ऐतिहासिक भूमिका रही है। जो नया है वह है कि इमरान खान फैक्टर के कारण शायद हमारे सामने इमरान खान जैसी चुनौती नहीं आई है जो 2002 से या जब से उन्हें सत्ता से हटाया गया है, तब से व्यवस्था के सामने मौज़ूद है।

इसका नागर-सैन्य संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान के संदर्भ में नागर- सैन्य संबंध महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सेना का प्रभुत्व जो ऐतिहासिक रूप से रहा है और अब इस बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस सीमा तक राजनीतिक व्यवस्था सेना द्वारा नियंत्रित है। मैं आपको जल्द ही कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे राजनीतिक विज्ञानियों ने पाकिस्तान को मॉडल बनाया है या पाकिस्तान में देश की प्रकृति को समझने की कोशिश में उन्होंने किस मॉडल का इस्तेमाल किया है। हमारे पास सबसे शुरुआती रूपरेखाओं में से एक पाकिस्तान को अति- विकसित देश की अवधारणा से समझने की कोशिश करना था। सेना का महत्व जो अनिवार्य रूप से बहुत ही अति- विकसित संस्था है, राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है।

साल 2008 से प्रोफेसर शाहिद (अश्रव्य) ने सैन्य-पश्चात आधिपत्य क्रम नाम की अवधारणा दी जो 2008 में जनरल मुशर्रफ के शासन के अंत के साथ एक नया चलन था और वह यह धारणा थी कि राजनीतिक प्रक्रिया वापस आ गई है। राजनेता अब अपना काम करने में सक्षम होंगे। मुझे लगता है सैन्य- पश्चात आधिपत्य क्रम कहना अभी भी उचित है क्योंकि आज हम जो देखते हैं वह यह है कि सेना का आधिपत्य

खत्म हो गया है। बेशक, यह एक ऐसा आकलन है जो हमें अब करने की आवश्यकता है कि हम देश में सेना के आधिपत्य को कैसे देखते हैं।

साल 2018 में जब से इमरान खान सत्ता में आए, कई लोगों ने पाकिस्तान में राजनीतिक व्यवस्था को एक हाइब्रिड शासन के रूप में समझने की कोशिश की है, जिससे हमें ऐसा लगा कि राजनेता और सेना एक ही स्तर पर हैं और शासन ठीक है, सरल है क्योंकि इन संस्थानों के बीच एक प्रकार का सामंजस्य है। लेकिन मैं एक और शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है, जिसकी पाकिस्तान में सेना की भूमिका पर कुछ झलक है, और वह शब्द है, निर्देशित लोकतंत्र, क्योंकि मेरी समझ में और यह एक बहुत ही गंभीर अवलोकन है, मुझे नहीं लगता कि सेना कभी भी पाकिस्तान में सत्ता, प्रत्यक्ष रूप से सत्ता अपने हाथ में लेने वाली है। मुझे लगता है कि वह दौर खत्म हो चुका है। हम शायद कभी सेना को सीधे कदम उठाते हुए न देखें क्योंकि देश पर शासन करना इतना मुश्किल हो गया है कि सेना के पास भी देश की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है।
सेना को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि वह एक शक्ति संरचना में हो, जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभुत्व के लिए महत्वपूर्ण है। निर्देशित लोकतंत्र, जिस कारण से मैं इसका उपयोग करता हूँ, वह सेना के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए, यह चुनावी लोकतंत्र का एक स्वरूप है कि पाकिस्तान में चुनाव होने चाहिए, चाहे उन चुनावों की वैधता का सवाल कुछ ऐसा हो जिस पर हम सवाल उठा सकते हैं लेकिन चुनाव महत्वपूर्ण हैं, मूलतः सेना ही यह तय करेगी कि पाकिस्तान में किस प्रकार की सरकार होगी और यह बात 2018 के चुनावों से लेकर बीते वर्ष 2024 के चुनावों तक स्पष्ट हो गई है।

लेकिन सेना की भूमिका, सेना का प्रभुत्व, सेना की क्षमता वास्तव में पाकिस्तान की राजनीति में जीवन से बड़ी भूमिका निभाने की, ने, वास्तव में नागरिक संगठनों को कमज़ोर कर दिया है। मेरा ऐसा कहने का मतलब है, इस संकट से कौन निपटेगा, सेना इससे निपट नहीं सकती, न ही यह राजनीतिक संस्थाओं को इससे निपटने देती है। इसलिए देश की वैधता में कमी आई है। देश में प्रभावी शासन संभव नहीं है और

यह वही है जो मैं हाल ही में देख रहा था, हंटिंगटन जिसने राजनीतिक क्षय नामक शब्द दिया था, के पुराने साहित्य को पढ़कर।

आज हम पाकिस्तान में जो देख रहे हैं वह एक प्रकार का राजनीतिक पतन है। यानि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में, यह माना जाता है कि संस्थाएं आगे बढ़ेंगी, आधुनिक बनेंगी। लेकिन वास्तव में, पाकिस्तान के संदर्भ में, इसके उलट हो रहा है। और वह यह है कि सत्ता संरचना में शामिल सेना के अलावा, आप सभी अन्य संस्थाओं में अनिवार्य रूप से राजनीतिक पतन देख रहे हैं। हंटिंगटन ने कहा, यह प्रगति के बजाय प्रतिगमन है, न कि राजनीतिक या सामाजिक प्रगति।

यह आधुनिकीकरण करने वाले देशों के साथ होता है। आधुनिक होते देश लाभ कमाने की क्षमता को खो सकते हैं और कई बार, एक संस्था में लाभ होने से दूसरी संस्थाएं कमज़ोर हो सकती हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में यही हुआ है। संस्था में लाभ, सैन्य संस्था ने अनिवार्य रूप से देश की सभी अन्य संस्थाओं को कमज़ोर कर दिया है, जिसके बीच हम हर चीज़ का सीधा संबंध नहीं बना पाएंगे। लेकिन इसके निहितार्थ स्पष्ट हैं। चाहे देश की राजनीति हो, चाहे देश में सद्भाव हो, या देश की अर्थव्यवस्था, हम देख सकते हैं कि ऐसी संस्थाओं का मुद्दा है जो विफल हो गई हैं या ऐसी संस्थाएं जो बदलती वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही हैं।

अब, इस परिदृश्य में, आज हम जो पाते हैं वह है पाकिस्तान में अस्थिरता। हम यह सवाल उठा सकते हैं कि अगर इमरान खान राजनीतिक व्यवस्था के लिए जिस तरह की चुनौती पेश कर रहे हैं, अगर वह चुनौती नहीं होती, तो शायद यह एक काल्पनिक सवाल है, कि शायद सेना मुद्दों या समस्याओं से निपटने में सक्षम हो सकती थी। इमरान की चुनौती अनिवार्य रूप से सभी को चौकन्ना कर रही है। चाहे वह राजनीतिक नेतृत्व हो या सेना। वे अनिवार्य रूप से नहीं जानते कि इससे कैसे निपटना है।

इसका संबंध पाकिस्तान के संदर्भ में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों से है। वे संरचनात्मक परिवर्तन कारक हैं और जिनके कारण मैं श्री देवाशेर से सहमत हूँ जब उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान उबर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि यह उबर पाएगा क्योंकि ये बदलाव एक नई गतिशीलता ला रहे हैं। इसलिए, ऐसा नहीं है कि हम पीछे जा सकते हैं। हम केवल आगे बढ़ेंगे। वैचारिक रूप से मैं जो तर्क दे रहा हूँ वह यह है कि हम केवल आगे बढ़ेंगे और समय के साथ और कमज़ोर होते जाएंगे। इसका मतलब है कि व्यवस्था पहले से भी अधिक कमज़ोर होती जाएगी। श्री देवाशेर ने फिर से जिन बदलावों की ओर इशारा किया, पाकिस्तान में जो जनसांख्यिकीय बदलाव हुए हैं, वे अनिवार्य रूप से बदलाव चाहते हैं।

आज आप पाते हैं कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सेना के खिलाफ जाना या बोलना चाहता है। ऐसे कहने से मेरा मतलब है कि सेना अब स्वीकार्य नहीं है। यह अलग बात है कि, सेना की पैठ अब भी सत्ता संरचना में है। यह इमरान खान के सामने आने वाली चुनौती के माध्यम से परिलक्षित भी हो रहा है। ऐसा क्यों है कि वह सड़क पर सत्ता लाने में सक्षम है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि, यह क्या है, उन्होंने एक आह्वान किया और मुल्क की आवाम सड़कों पर उतर आई और सेना एवं सुरक्षा बलों को चुनौती देने की कोशिश कर रही है।

इसलिए, इसका अध्ययन जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, जो पाकिस्तान में हुए हैं और मेरे पास जो कुछ डेटा है। 35% आबादी 15 वर्ष से कम है। 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की आबादी 63% है। लेकिन इस समूह में साक्षरता दर केवल 50% है। इसलिए आज पाकिस्तान में एक महत्वाकांक्षी वर्ग है जो आर्थिक समस्याओं से, सत्ता संरचना में सेना की पैठ से बहुत परेशान है। और इमरान खान एक अलग दृष्टिकोण देने में कामयाब रहे, चाहे वह सही हो या गलत, जिसके द्वारा वह समस्याओं से निपटने के तरीके के बारे में एक नज़रिया देकर अपने लिए एक समर्थन आधार बनाने में सफल रहे हैं।

इमरान ने भले ही पाकिस्तान की समस्याओं को आसान बना दिया हो लेकिन उनके शासन के कुछ सालों में हमें इस बात के पर्याप्त संकेत भी मिले कि इमरान के पास भी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। न तो उनके पास कोई विज़न है और न ही कोई नीति। लेकिन उनका तरीका, भाषा या जिसे कोई भी कह सकता है, वह मुहावरों का इस्तेमाल करता है कि वह सेना को कैसे चित्रित करता है या वह राजनीतिक नेतृत्व, वंशवादी राजनीति, भ्रष्टाचार विरोधी को कैसे चित्रित करता है। एजेंडा- एक महत्वपूर्ण एजेंडा भ्रष्टाचार विरोधी, वंशवादी राजनीति, सामंती राजनीति विरोधी है। यह सब आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संगठित करने की उनकी क्षमता में अहम रहा है।

आज इमरान का समर्थन आधार दोनों क्षेत्रों में है। शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक, यह किसी खास वर्ग तक सीमित नहीं है। लेकिन इन सब में इमरान का उद्देश्य क्या है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे पाकिस्तान के संदर्भ में और सत्ता में आने वाले सैन्य शासन के संदर्भ में उठाया जाना चाहिए। सैन्य शासन सत्ता में इसलिए भी आया क्योंकि राजनेताओं ने उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए अनुमति दी है या अनिवार्य रूप से सेना का इस्तेमाल किया है।

इसलिए, आज इमरान का उद्देश्य यह नहीं है कि वह वास्तव में सेना और राजनीतिक अभिजात वर्ग या राजनीतिक वर्ग के बीच संतुलन बदलने जा रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल सत्ता में वापस आना है। भले ही, मेरे कहने का मतलब है, वह भाषा का प्रयोग करने में सक्षम रहे हैं, वे चुनावों की वैधता के सवालों का उपयोग खुद के लिए बेहतर माहौल बनाने में सक्षम रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य मूलतः सत्ता में वापस आना है। वह नागर- सैन्य समीकरणों में असंतुलन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे मूलतः सत्ता में वापस आने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

इसलिए, अगर आने वाले कल में सेना कहती है, उन्हें राह दिखाती है और बताती है यह तरीका है जिससे आप सत्ता में वापसी कर सकते हैं तो वे फिर से सेना से हाथ मिलाने पर बहुत खुश होंगे। आज के समय

में सेना की वैधता कम हो गई है और यही सेना की सबसे बड़ी समस्या भी है। वैधता में कमी के कई कारण है- चाहे वह चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हो या फिर कुछ विवादास्पद न्यायिक फैसलों से। वास्तव में आज सेना के खिलाफ़ आवाम में आक्रोश है और इमरान ऐसा करवाने में समर्थ हैं।

तो, आने वाले कुछ सालों के लिए मेरा पूर्वानुमान, पहला, यह कि सेना को यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि वे इमरान खान के सामने न झुकें। ऐसा हो पाएगा या नहीं, यह इमरान खान द्वारा की जाने वाली राजनीति पर निर्भर करेगा। सेना के खिलाफ़ सड़कों पर ताकत का इस्तेमाल करने के लिए इमरान के पास कौन सी नई रणनीति है। क्या उनके पास कुछ और भी है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि, उन्होंने सैन्य आर्थिक अवसंरचना आदि का बहिष्कार करने के बारे में कुछ कहा है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मेरे अपने संदेह हैं। यह मुख्य रूप से इस बारे में होगा कि इमरान सेना पर कितना राजनीतिक दबाव डाल पाते हैं।

सेना बदलाव की अनुमति नहीं देगी क्योंकि इससे उनके असफल होने का संदेश जाएगा। इससे चुनावों की वैधता पर सवाल उठेंगे। इससे देश पर शासन करने में सेना की विफलता का भी पता चलेगा। तो, इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि यहाँ एक ऐसी सेना है जिसके पास समस्याओं का समाधान नहीं है। यहाँ एक ऐसी सरकार है जो सत्ता में तो है लेकिन उसके पास वास्तव में कोई अधिकार नहीं है। वह पाकिस्तान की समस्याओं को दूर नहीं कर सकती।

इसलिए, पाकिस्तान में जो संकट हम देख रहे हैं, वह संभवतः और भी अधिक बढ़ जाएगा। यह मेरे गुरु से उधार लिया गया मेरा सिद्धांत है। वह अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा देश है जो राजनीतिक पतन की स्थिति में है। उस राजनीतिक पतन को कैसे रोका जाए, यह एक बेहद क्रांतिकारी विचार है और वह यह है कि सेना को सत्ता से बाहर होना चाहिए जो पाकिस्तान के संदर्भ में कभी नहीं होने वाला है।

अनिल त्रिगुणायत: हंटिंगटन का हवाला देने और पाकिस्तान में मूल रूप से सैन्यतंत्र के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोफेसर बेहरा आपका धन्यवाद। सेना जो पाकिस्तान में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति और देश की कर्ताधर्ता भी है, उसे आसानी से जाने नहीं देगी। हमने देखा है कि हाल ही में आईएसआई के पूर्व प्रमुख फ़ैज अमीन को ज़मीन हड़पने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था लेकिन हम यह भी देख रहे हैं और शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि पीटीआई और नवाज़ शरीफ की पीडीपी पार्टी के बीच बातचीत शुरू हो गई है और इससे पहले, मुझे लगता है, 2 जनवरी को, इनके बीच दूसरे दौरा की वार्ता हुई थी। शायद अब हर कोई जीवन जीने का तरीका ढूंढ़ने का प्रयास कर रहा है क्योंकि इमरान खान शायद पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने आकाओं को चुनौती दी जिन्होंने उन्हें सत्ता में लाया था। और यही हुआ। उन्हें काफी हद तक कमज़ोर करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के अंदर सेनाओं को कमज़ोरियां साफ़ तौर पर दिखाई दे रही थी।

तो, यह कैसे होता है और आप बिल्कुल सही हैं। एक बात जो आपने सुझाई वह यह है कि पाकिस्तान वास्तव में बहुत नीचे जा रहा है और शायद इसके भीतर किसी तरह का विस्फोट होना चाहिए, जो शायद पहले से ही हो रहा है। लेकिन यह थोड़ा ख़तरनाक होगा और हमें इसे समझना होगा। और उन्होंने दो बातों पर भी बात की। डॉ. चावला, संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन के बारे में। आप इसके निहितार्थों को किस तरह देखती हैं? और दूसरा, आर्मी एक्ट में बदलाव। मूल रूप में सेना प्रमुख के कार्यकाल को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया जाना और मुझे लगता है कि चार- सितारा जनरलों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जानी चाहिए।

इसलिए, मैं डॉ. शालिनी चावला जिन्हें हम सभी सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ में इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जानते हैं, अनुरोध करूँगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें।

शालिनी चावला: धन्यवाद, महोदय। महानिदेशक महोदय, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा अवसर हमेशा खुशी प्रदान करता है। ज़ाहिर है, मुझे अंतिम वक्ता होने का थोड़ा नुकसान तो है। ज्यादातर मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में, मुद्दे कभी खत्म नहीं होते और आपके पास कवर करने को कुछ- न- कुछ हमेशा होता है। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा कही गई बात, कि पाकिस्तान के पास उपद्रवी मूल्य है, से शुरुआत करुँगी। और साथ ही, श्री देवाशेर ने इस तथ्य के बारे में बात की कि उसने अपनी भोगोलिक स्थिति को कैसे संजोया है।

मुझे लगता है कि इस समय सबसे बड़ी चुनौती, जिसका सामना एक देश के रूप में पाकिस्तान खुद कर रहा है, और यह हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है लेकिन इस देश पाकिस्तान के लिए चुनौती है क्योंकि दशकों से ये यही कहानी गढ़ता आया है कि यह एक ऐसा देश है जिसका असफल होना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि यह भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण देश है, चीन और अमेरिका के लिए इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से भी यह बहुत महत्वपूर्ण देश है। फिर इसके पास परमाणु हथियार भी हैं। देश में आतंकवादी संगठनों की संख्या भी सबसे अधिक है। अफ़गानिस्तान के साथ इसकी सीमा है और यह पूरा क्षेत्र आतंकवाद का केंद्र रहा है।

इसलिए विश्व पाकिस्तान को डूबने नहीं दे सकता। यही वह कहानी और भरोसा है जिसे पाकिस्तान ने दशकों से बनाया है। और उसे हमेशा लगता था कि चाहे वह किसी भी संकट की स्थिति में कितनी भी बुरी स्थिति में पहुँच जाए, पाकिस्तान को मदद और सहायता मिल ही जाएगी। मुझे लगता है कि संकट के इस दौर ने उस विश्वास को चुनौती दी है जहाँ पाकिस्तान सच में आर्थिक चूक की कगार पर खड़ा था, उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से ऋण प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। यह सहायता प्राप्त करना आसान नहीं था। शर्तें बहुत कठोर थीं जो बिल्कुल सही भी थीं, पाकिस्तान जैसे देश के लिए जो बार- बार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास मदद के लिए जा रहा था।

इसलिए इस बार उसे मदद इतनी आसानी से नहीं मिली जितनी आसानी से मिल जाने की उसे उम्मीद थी। यह सुरक्षा स्थिति पर प्रकाश डालता रहा है, हमलों के बारे में बात करता रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से सुरक्षा मदद इसे नहीं मिली है। तो ऐसा कुछ तो जरूर है जिससे पाकिस्तान जूझ रहा है और मुझे लगता है कि अमेरिका के हाथ खींचने के बाद, जैसा कि श्री देवाशेर ने कहा है, इसकी प्रासंगिकता में कमी आई है। हिंद- प्रशांत रणनीति पर अमेरिका का फोकस स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के लिए उस हिस्से को नुकसान पहुँचाया है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं जिन मुद्दों पर बात कर रही हूँ और पाकिस्तान में जारी अस्थिरता में भारत का उदय भी एक कारक रहा है।

इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अपने लिए उस प्रासंगिकता को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष कर रहा है। हम पाकिस्तान में जो देख रहे हैं, जहां से संकट को उजागर किया जा रहा है और प्रोफेसर बेहरा ने इस तथ्य के बारे में बात भी की है, स्थिति बद- से- बदतर होती जा रही है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ यही कहूँगी कि पाकिस्तान उलटाव की राह पर चल पड़ा है। यह प्रगतिशील देश के मूल्यों से पीछे की ओर जा रहा है, जिसे किसी समय शायद यह छूने में कामयाब रहा हो और वह इसके बारे में बात कर रहा था।

इसलिए, हम इस देश में एक विरोधाभास देखते हैं जो एक सैन्य रूप से आधुनिक देश है, जिसके पास सबसे तेज़ी से बढ़ते परमाणु शस्त्रागार हैं, जो दावा करता है कि उसके पास एमआईआरवी (MIRV) मिसाइलों के निर्माण की क्षमता है, जिसे उसने लॉन्च किया। यह सबसे बड़ी शक्तियों में से एक चीन का सहयोगी है, बीते 40, 50 वर्षों से लगातार रणनीतिक सहयोगी रहा है। वह लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी रहा है, लेकिन इन सभी गठबंधनों का उपयोग सिर्फ सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया है और इसका परिणाम हम अब देख रहे हैं।

इसलिए कई मोर्चों पर संकट हैं और मैं उनमें से कुछ पर बहुत जल्द अपने विचार रखने वाली हूँ। पहला, जिसे प्रोफेसर बेहरा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, स्पष्ट रूप से लोकप्रिय जनादेश की हार और हाइब्रिड शासन को मजबूत करना, उसी की निरंतरता है। इसलिए इस कार्यकाल में, हमने देखा, हाइब्रिड शासन, जिस तरह से यह आया, अब बदलने में कामयाब रहा है, संवैधानिक संशोधन को भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती को रोकने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए, 26वां संशोधन जिसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने सवाल उठाया था, ने स्पष्ट रूप से सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार को चुनौती दी है।

इसने न्यायपालिका की सेना को लंबे समय तक चुनौती देने की क्षमता को चुनौती दी है, क्योंकि अब न्यायाधीशों का चयन संसदीय समिति द्वारा किया जाएगा और उन्हें तीन न्यायाधीशों में से चुना जाएगा, न कि अनिवार्य रूप से वरिष्ठ न्यायाधीश से। इसके अलावा, इन परिवर्तनों का तात्पर्य यह है कि सेना प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार हुआ है और कई अन्य कारक भी सामने आए हैं जिससे उनकी क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और अब पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है।

इसलिए हम देखेंगे कि इसका गहरा असर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा असर जो हम यहाँ देख रहे हैं, वह यह है कि इस बहुत मजबूत सैन्य शासन के साथ शरीफ सरकार पर दबाव हो, जो जारी रहेगा और उनकी क्षमता, शाहबाज़ शरीफ़ की देश के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाले निर्णय लेने की क्षमता क्योंकि अब इस शासन का पूरा ध्यान अपनी स्थिरता पर है। इसलिए वह अपनी स्थिरता बनाए रखना चाहता है और इसके लिए उसे सेना की नज़र में अच्छा बने रहने की जरूरत है। इसलिए इस पर फोकस किया जाता है और जन- केंद्रित नीतियों पर इस बात पर फोकस नहीं दिया जाता।

मुझे लगता है कि यह सबसे प्रमुख संकटों में से एक है, और सेना अधिनियम, गोपनीयता अधिनियम और 26वें संशोधन अधिनियम के पारित होने से देश में सत्ता की गतिशीलता में और बदलाव आया है, जिससे सेना को और अधिक मजबूत पकड़ मिली है और असीम मुनीर की अगुआई में नेतृत्व ज़ारी रहा, जहाँ अब

उनके पास स्थिति को अपने पक्ष में करने की क्षमता होगी। सेना की छवि को चुनौती दिए जाने का संकट, जिस तरह से दशकों से उसका दर्जा बरकरार है, वह शायद सबसे निचला स्तर है जिसे हमने देखा है और उन पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसलिए मैं इस पर विस्तार से नहीं बात करूँगी लेकिन एक सवाल था जो वक्ताओं के रूप में हमसे पूछा गया था- उस छवि को नुकसान क्यों पहुँचा?

जी हाँ, निश्चित रूप से इमरान खान एक कारक हैं लेकिन यह गहरा अहसास कि देश में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के लिए सेना उत्तरदायी है, पहले से कहीं अधिक है और बहुत मुखर भी। सेना के भीतर भी फूट पड़ी है। मुझे लगता है इससे सेना की छवि खराब हुई है। पहली बार संस्था इतनी धुव्रीकृत हुई है। आपको याद होगा कि वहाँ इमरान समर्थक और इमरान विरोधी गुट, जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा था, देखने को मिला और शीर्ष नेतृत्व में भी अपने साथियों और विरोधियों को लेकर लगातार अविश्वास बना हुआ था। इस ध्रुवीकरण के कारण, हमने पहली बार पूर्व आईएसआई प्रमुख फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल देखा, जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

तीसरा, टीटीपी द्वारा सेना को बार- बार निशाना बनाया गया है। ऐसा भी कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बीते साल करीब 900 हमले हुए, मान लें कि हर महीने 50 या 60 से अधिक हमले, हिसाब लगाएं तो सैन्य प्रतिष्ठानों पर हर दिन लगभग डेढ़ या दो हमले। ये ऐसे आंकड़े हैं जो आवाम में उनकी विश्वसनीयता को चुनौती देते हैं, अपने ही प्रतिष्ठानों की रक्षा करने में असमर्थता साबित करते हैं और अफगान तालिबान द्वारा सेना को खुलेआम चुनौती देने एवं उनकी अपीलों, दबावों की अवहेलना को दर्शाते हैं। पाकिस्तान ने सब कुछ कर के देख लिया, व्यापार में कटौती कर दी, व्यापार शुल्क में इज़ाफा कर दिया, सीमाओं को बंद कर दिया, अफगानिस्तान के शरणार्थियों को निर्वासित भी किया लेकिन अफगान तालिबान पर इनका कोई असर नहीं हुआ।

मुझे लगता है कि इमरान खान की लोकप्रियता के साथ- साथ इन कारकों का संयोजन सेना की इस खराब छवि का कारण है, और हम देख रहे हैं कि सेना अपनी छवि को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। अगला जो संकट है- एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो मेरी राय में बहुत महत्वपूर्ण है, वह है सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर बनाने के लिए मौलाना फ़जल- उर- रहमान के जेयूआईएफ (JUIF) का हाल ही में संविधान के 6ठे संशोधन को पारित करने में सरकार का साथ देना। वे विधेयक, जिसे अब संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और जो सोसायटी पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2024 के नाम से जाना जाता है, को लागू करने के मुद्दे पर सरकार से असहमत हैं और इसका उद्देश्य, स्पष्ट रूप से इस विधेयक का अर्थ इसके विपरीत है, यानि धार्मिक पाठशालाओं के पंजीकरण को संघीय शिक्षा प्रणाली से परंपरागत पंजीकरण प्रणाली में लाना है।

इसलिए, 2019 में पाकिस्तान में कुछ सुधार लागू किए गए और इसलिए मैंने कहा कि यह एक परिवर्तन की स्थिति में है, जिसने इन पाठशालाओं (मदरसों) को शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में रखा, मंत्रालय को आंकड़े जुटाने, नियंत्रण करने, निगरानी करने, उनके पाठ्यक्रम पर नज़र रखने के साथ- साथ इस बात पर नज़र रखने के लिए एकमात्र प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्रदान की गई कि वे नफ़रत न फैलाएं और उनके वित्त पर भी नज़र रखे। यह पूरी प्रक्रिया जो उस समय पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रेलिस्टिंग के दबाव में किया गया था, को बदल दिया गया है। फिर, यह उनके समग्र प्रयास के संदर्भ में एक कदम पीछे जाना है, जिसे हम चरमपंथ का मुकाबला करने के संदर्भ में देखते हैं और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है।

एक और संकट है जो मुझे लगता है कि इस समय नया है, और वह यह है कि पहली बार सभी चार प्रांतों और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसलिए, पंजाब में स्पष्ट रूप से लोकप्रियता संबंधी मुद्दे थे, जहाँ नवाज़ शरीफ़ को वाकई तथाकथित जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा, अगर यह वास्तव में उनके लिए जीत थी। तब से लेकर अब तक वहां विरोध प्रदर्शन जारी है क्योंकि वहां 50,000

एकड़ भूमि, प्रस्तावित छह नहरों के निर्माण और ख़ैबर- पख़्तूनख़्वा, बलूचिस्तान पर सेना ने कब्ज़ा कर लिया है, ख़ैर, हम टीटीपी पर बार- बार हमला होते देख रहे हैं, और इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है।

आर्थिक संकट, जो बहुत महत्वपूर्ण है, चिंताजनक है। मुझे लगता है कि कर्ज़ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह अभूतपूर्व स्तर पर है और 70,366 अरब रुपये है जो हमने पाकिस्तान को इतने बड़े कर्ज़ में कभी नहीं देखा है। इसलिए, आर्थिक संकेतकों में कुछ बदलाव हुआ है। जीडीपी 2.4% हो गई है, मुद्रीस्फीति 29% से घटकर 23% पर आई है, लेकिन क्या यह वास्तव में आर्थिक विकास का संकेत है? नहीं, क्योंकि यह किसी भी तरह से आर्थिक कुप्रबंधन में बदलाव का संकेत नहीं देता है और इसके लिए, ज़ाहिर है, स्थिरता, संरचनात्मक परिवर्तन की जरूरत है। मानव पूंजी और विकासात्मक पहलूओं में पाकिस्तान को निवेश की आवश्यकता है, गैर- विकास व्यय जैसे रक्षा क्षेत्र में कटौती की आवश्यकता है जिसे कभी सामने नहीं लाया गया और बजट में भी सही आंकड़े नहीं दिखाए जाते हैं।

कुछ निवेश, जिन्हें वे करना चाहते हैं, की संभावनाएं हैं, लेकिन इतनी अधिक अस्थिरता की वजह से मुस्लिम विश्व, यूएई और सऊदी अरब से कितना निवेश आएगा, अभी देखना बाकी है। अब, मेरा आखिरी मुद्दा, और जल्दी से मैं इस पर अपने विचार रखती हूँ- यह संकट पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है और बड़े स्तर पर हम इसे अपने व्यावहारिक स्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करते और प्रतिबिंबित होते देखते हैं?

मुझे लगता है कि एक अलग बात होगी, हम देखेंगे कि वह मुस्लिम विश्व के करीब आने की कोशिश करेगा, वहां से आर्थिक लाभ प्राप्त करेगा। हमने सऊदी अरब, यूएई, तुर्की के साथ आतंकवाद विरोधी अभ्यास, सैन्य अभ्यास करते पाकिस्तान को देखा है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खुद को अमेरिका का सहयोगी साबित करने की कोशिश करेगा। दूसरे क्षेत्रों जैसे- बालिकाओं की

शिक्षा, क्षेत्र के कुलपतियों से मुलाकात करना, में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए इस भाग में हम मुस्लिम विश्व से सौहार्द स्थापित करने के प्रयास देखेंगे, इससे रिश्तों को मजबूत होता देखेंगे।

दूसरा हिस्सा भी दिलचस्प है, मुझे लगता है कि ट्रम्प के आने से यह बात सामने आएगी। पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ अमेरिका के सहयोगी के रूप में पेश करना चाहेगा। टीटीपी द्वारा परमाणु ऊर्जा कर्मियों के अपहरण, जिसके बारे में अभी- अभी ख़बर आई है कि 16 कर्मियों का अपहरण किया गया है, माना जाता है यह एक झूठा अभियान है जो जाहिर तौर पर वहां की खुफिया एजेंसी द्वारा किया गया था जो टीटीपी एवं सुरक्षा स्थिति के मुद्दों पर अमेरिका और सीआईआई का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक और कारक होगा जिसे हम देखेंगे।

इसके अलावा, भारत के खिलाफ उसकी स्थिति, भारत के खिलाफ गुप्त युद्ध पर उसकी निर्भरता, मुझे नहीं लगता कि हम इसमें किसी तरह का बदलाव देख पाएंगे। लेकिन हाँ, हम पाकिस्तान में और अधिक अस्थिरता देखेंगे, भारत विरोधी रुख पर उसकी निर्भरता बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।

अनिल त्रिगुणायत: डॉ. चावला बहुत कम समय में आपने बहुत विस्तृत जानकारी दी, आपका बहुत- बहुत धन्यवाद। आपने लगभग सभी मुद्दों को कवर किया है और मेरा मानना है कि इसमें एक और मुख्य मुद्दा है- भले ही सुधार हो रहे हों लेकिन वे रुझानों को उलट रहे हैं। सुधार प्रगतिशील नहीं हैं। इसलिए जो सुधार हो रहे हैं, वे नकारात्मक तरीके से हो रहे हैं, जो महत्वपूर्ण हैं। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए वह यह कि पाकिस्तान की प्रासंगिकता, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, भारत के उदय से जुड़ी हुई है लेकिन साथ ही, हमें यह भी देखना होगा कि यह किस रूप में सामने आती है।

आपने इस बात का उल्लेख किया कि पाकिस्तानी खुद को ईरान का विरोधी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से गलत साबित होने जा रहा हूँ। इस क्षेत्र में नए समीकरण विकसित

हो रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा अंततः ये चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की के ताक प्रारूप का हिस्सा बन सकता है। आखिर में हम उन्हें उस विशेष दिशा में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। जैसा कि आपने बताया, वे सहयोग या मदद के लिए इस्लामी विश्व में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस्लामी विश्व भी विकसित हो चुका है, विशेष रूप से सऊदी अरब और यूएई, मुझे लगता है कि वे प्राचीन वहाबी शैली की ओर जाने की बजाय विकासोन्मुख, आधुनिकीकरणोन्मुख हैं।

इसलिए उन्हें इन देशों से पैसे और मदद प्राप्त करने में अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक ट्रम्प या पाकिस्तान का सवाल है, ट्रम्प का मूल उद्देश्य किसी तरह डीप स्टेट का बचाव करना है। लेकिन जहाँ तक डीप स्टेट का सवाल है, जो वास्तव में बहुत गहरा है, वे पाकिस्तान को खुश करना जारी रखेंगें और इसे अपने लिए एक संकेतक के रूप में बनाए रखेंगे। शायद हम इसके होने के गवाह बनें। इसके अलावा, निश्चित रूप से, अर्थव्यवस्था ने थोड़ा बदलाव दिखाया है, सकारात्मक बदलाव। और हमें देखना होगा, जहाँ तक ऋण और उससे संबंधित सभी चीजों का सवाल है, मुझे लगता है कि सोना मिलने की ख़बर सुर्खियों में बहुत नहीं रही। उन्हें हाल ही में सोने का ख़दान मिला है जिसमें सात अरब डॉलर ($7 billion) मूल्य के सोना होने की बात कही जा रही है। आशा है इससे उनके देश को थोड़ी और मदद मिल सकेगी।

अब मैं प्रश्नोत्तर सत्र की शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे पास 25, 30 मिनट का समय है। और हम पांच बजे सत्र समाप्त कर देंगे। इसलिए अपना परिचय दें और आप किससे सवाल करना चाहते हैं, यह भी बताएं। कृपया पीछे बैठी महिला अपना प्रश्न पूछें।

वरिष्ठा: आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वरिष्ठा है। मैं यहाँ एक रिसर्च इंटर्न हूँ।

अनिल त्रिगुणायत: क्या आप संक्षेप में सवाल पूछ सकती हैं?

वरिष्ठा: मेरा सवाल तिलक सर से है? क्या आप पाकिस्तान में राजनीति से शासन की ओर बढ़ते युवाओं की भागीदारी को देख पा रहे हैं और क्या उनमें इसकी चुनौतियों से निपटने की क्षमता है? और अजय सर से मैं यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि विभिन्न जातीय संघर्षों के कारण पाकिस्तान की पहचान कमज़ोर हुई है? क्या राजनीतिक पतन ने उसकी पहचान को कमज़ोर बनाया है और संघर्षों को बढ़ा दिया है? शालिनी मैडम से मेरा सवाल है कि इन सब का निहितार्थ क्या है?

अनिल त्रिगुणायत: कृपया एक बार में एक ही सवाल पूछें।

वरिष्ठा: जी हाँ, दक्षिण एशिया के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं? और क्या आप पाकिस्तान की महिलाओं को ईरान में महिला प्रतिरोध आंदोलन से प्रेरणा लेते और बेहतर जीवन एवं अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हुए पाते हैं?

तिलक देवाशेर: दो सवालों के जवाब दूंगा।

अनिल त्रिगुणायत: ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। अच्छा। कृपया एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछें।

सर्वजीत डुडेजा: धन्यवाद सर। मुझे लगता है हम हमेशा पाकिस्तान में संकट की ही बात करते हैं। बड़े भाई- विश्व गुरु या विश्व मित्र होने के नाते, क्यों न उन्हें कोई समाधान दिया जाए, जिस तरह भारत ने सफलता प्राप्त की, उसी तरह का? वे हमसे भी तो सीख सकते हैं, चाहे वह चार स्तंभ हो या वे इसे दोहरा सकते हैं। हम हमेशा दूसरी समस्याओं की बात करते हैं। समस्या के बारे में बात करने की बजाए उन्हें समाधान क्यों नहीं दे देते? उनके पास सिंध की समस्या है, बलूचिस्तान की समस्या है। उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। और वे भारत से सबक ले सकते हैं। आखिरकार, हम पाकिस्तान के बड़े भाई हैं।

अनिल त्रिगुणायत: महोदय, इस विषय में हम दिलचस्पी रखते हैं, शायद राष्ट्र हित उनकी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस विषय पर बात की गई है लेकिन भारत उन्हें कुछ भी बता नहीं सकता। हम केवल मदद कर सकते हैं। हम सहायता कर सकते थे। महामारी के समय हमने उनकी मदद भी की। और आप अगर गलत काम करने जा रहे हों और किसी की भी सुनने को तैयार न हों तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जी, एक और सवाल। हाँ जी, आप पूछिए।

अज्ञात प्रतिभागी: तो मेरा सवाल है कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के गठन के पीछे मूल रूप से दो अलग देश एवं अलग और विशिष्ट मुस्लिम पहचान का विचार है। लेकिन अगर हम हाल के वर्षों पर नज़र डालें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में पहचान का संकट चल रहा है। मूल रूप से पाकिस्तान में इसी आधारभूत विचार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और हम इसे पाकिस्तान में बलूच और अहमदियाओं के उत्पीड़न में देख सकते हैं। तो मेरा सवाल बेहरा सर के लिए है। पाकिस्तान के राजनीतिक परिदृश्य में सामंजस्य को चुनौती देने वाले इस पहचान संकट को हम कैसे देख सकते हैं?

अनिल त्रिगुणायत: ठीक है**,** धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न।

संदीप: महोदया और महाशय नमस्कार। मेरा नाम संदीप है। मैं किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक कर रहा हूँ, मेरा विषय राजनीति विज्ञान है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना, जो अक्सर भारत के साथ वार्ता में बाधा डालती है, की, प्रमुख भूमिका को देखते हुए क्या पी2पी (P2P) संबंध को मजबूर करना द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का वैकल्पिक रास्ता हो सकता है? भारत ने अफ़गानिस्तान के साथ सांस्कृतिक, शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे से संबंधी पहलों का सफलतापूर्वक उपयोग का है और पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह का दृष्टिकोण राजनीतिक बाधाओं को दूर करने, आपसी समझ और दीर्घकालिक सहयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। महोदय, एक और सवाल। पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियों

के बीच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच विकसित होते संबंधों को आप किस तरह देखते हैं? क्या यह साझेदारी पाकिस्तान को उसके संकट को कम करने में मदद कर सकती है?

तिलक देवाशेर: धन्वाद। तो पहला सवाल जो आपने पूछा वो मूल रूप से राजनीति में युवाओं की भागीदारी से संबंधित था, है ना? पाकिस्तान में राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक नेतृत्व सीमित कार्यक्षमता जैसा है। आप पीएमएल और मुस्लिम लीग को ही ले लें, यह शरीफ का परिवार है और केवल पार्टी में उनके बच्चों, बेटों के लिए ही अवसर उपलब्ध हैं। ऐसा ही हाल टीटीपी में भी है। केवल पीटीआई थी जिसने लोगों को उनसे जुड़ने का मौका दिया, लेकिन इसमें भी केवल इमरान खान के करीबी ही नेतृत्व या सत्ता में हैं। तो क्या हुआ अगर युवाओं में राजनीति में आने और देश की राजनीति का हिस्सा बनने का उत्साह है, शासन के मामले में मुझे नहीं लगता कि ऐसा आने वाले कुछ समय तक होने वाला है। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक पाकिस्तान में राजनीतिक दलों का मॉडल नहीं बदल जाता।

वास्तव में, सेना के हावी होने का एक कारण यह है कि राजनीतिक दल स्वयं लोकतांत्रिक नहीं हैं। वास्तव में चुनाव नहीं होते, कोई संगठन नहीं है, कोई जिला स्तरीय पार्टी संगठन भी नहीं है। आज भी प्रत्येक जिले में एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है, आज वो मुस्लिम लीग का हिस्सा है, कल टीटीपी में जा सकता है और अगले ही दिन वो पीटीआई भी ज्वाइन कर सकता है। इसलिए ज़मीनी स्तर से ऐसा कोई भी नहीं जो सामने आ रहा हो और युवाओं को शासन में लाने में सक्षम हो।

शालिनी चावला: सर, सोने के बारे में थोड़ा हल्के- फुल्के अंदाज़ में कुछ कहना चाहूँगी, जब आपने कहा तो मैं कहने वाली थी कि शरीफ़ अपना सोना बेचने के लिए ले गए होंगे, शायद यही सोने की खोज़ प्रणाली है। दक्षिण एशिया से संबंधित सवाल, इसका दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, के बारे में कहूँ तो मुझे लगता है कि सबसे पहले निश्चित रूप से सुरक्षा कारक, जहां आपके पास दुस्साहसी टीटीपी है तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा ही। चीजें यहीं तक सीमित नहीं है। आपके पास पहले से ही मध्य एशिया में

एक गुट है और आपके पास टीटीपी तो है ही, इस तरह के मॉडल धीरे- धीरे सामने आ रहे हैं। इसलिए यह ख़तरनाक है।

इस प्रकार की अस्थिरता से आईएसकेपी (ISKP) को स्पष्ट रूप से अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन दक्षिण एशिया पर दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारक यह होगा कि आम चुनौतियों को सुलझाने के लिए किसी भी संभावित बातचीत के लिए जगह कम होती जा रही है। अब अगर आपके पास इस प्रकार की अस्थिरता है, पाकिस्तान- अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान- भारत, तो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए किसी भी चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है जिसके लिए आर्थिक एकीकरण या कनेक्टिविटी के मामले में किसी तरह की बातचीत और वार्ता की आवश्यकता होगी। इसलिए इनमें से कई परियोजनाएं अभी भी चल रही हैं। इसलिए भविष्य में इस प्रकार की चुनौतियां सामने आएंगी।

आपका दूसरा सवाल था कि क्या पाकिस्तान की महिलाएं उनसे प्रेरणा ले सकती हैं, मुझे लगता है कि इस समय जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान के पुरुषों के पास भी अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शनों को किस तरह शांत किया जा रहा है, बलूचों के साथ कैसा सलूक हो रहा है, युवाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। सेना के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को बहुत क्रूरता के साथ दबा दिया जा रहा है। लेकिन आपकी बात पर गौर करें तो बीते सात- आठ महीनों में देश खुद का महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। मरियम शरीफ़ को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया है।

आप इस प्रकार के घटनाक्रम देख रहे हैं और वे इस तथ्य की भी बात कर रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान को मान्यता नहीं देंगे क्योंकि वहाँ भी महिला अधिकारों की मांग हो रही है। इसलिए बहुत संघर्ष हो रहा है। महिलाएं कितनी मुखर हो सकती हैं, मुझे लगता है कि यह केवल महिलाओं के बारे में ही नहीं है, यह

वर्तमान में पीड़ित आम जनता के मुखर होने के बारे में भी है। तो यही यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका हम सामना करते रहेंगे।

जिस मुद्दे पर बात की गई, लोगों - से- लोगों के बीच संपर्क के बारे में, एक सवाल यह था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के मामले में यह मुश्किल है क्योंकि नीतियों में लोगों की बिल्कुल भी झलक नहीं मिलती। यदि आप लोगों- से- लोगों के बीच संपर्क करने का प्रयास भी करें, तब भी, सबसे पहले, वर्तमान समय में ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। वज़ह है वीज़ा और जिस तरह के संबंध दो देशों के बीच है। साल 2016 के बाद से ही हमारे बीच कोई कूटनीतिक संवाद नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान से वार्ता नहीं की है।

इसलिए लोगों- से- लोगों के बीच संवाद, नीतिनिर्माण में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में लोगों की भावनाएं या विकल्प नीति निर्माण में किसी भी तरह से प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि तीनों अध्यक्ष समेत, इसी बारे में बात कर रहे हैं, कि यह एक बहुत ही अलग देश है जो सामने आया है और जैसा कि अजय ने कहा, निर्देशित लोकतंत्र या निर्देशित लोकतंत्र के बारे में बात की। इसलिए पाकिस्तान के मामले में, मुझे लगता है कि इसके काम करने की संभावना कम है। हमने पहले भी इसे आज़माया है। हमने क्रिकेट मैच खेले हैं। हमने अमन की आशा की। हमारे प्रधानमंत्री 2015 में लाहौर गए थे और फिर हमारे पठानकोट पर हमला किया गया। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि यह पाकिस्तान के मामले में काम करेगा।

अनिल त्रिगुणायत: देखिए, जब भी कोई प्रयास किया जाता है तो उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है- दर्ज किया जाता है कि एक चर्चा या बैठक होने वाली है, और फिर आप पर आतंकवादी हमला कर दिया जाता है। है ना। तो ऐसा आप कितनी बार कर सकते हैं? और पी2पी कॉन्टैक्ट कहकर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लोगों को सब पता है। हम वही लोग हैं। लेकिन वे जिस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, आखिरकार,

दोंनों देशों के लोग इस तरह बात नहीं कर सकते। इसे देश- से- देश का संबंध होना चाहिए। और पाकिस्तान से हमें एक ही परेशानी है और कोई दूसरी परेशानी नहीं और वह परेशानी है आतंकवाद, उन्हें अपनी ज़मीन से आतंकवाद को नियंत्रित करना ही चाहिए। वे इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। भारत के लिए बस यही एक चिंता का विषय है। और कुछ भी नहीं। बाकी सब कुछ भुलाया जा सकता है।

अजय दर्शन बेहरा: जी हाँ। जातीय संघर्ष और राजनीतिक पहचान से संबंधित दो सवाल पूछे गए थे, लेकिन दोनों ही सवाल एक जैसे ही है। देखिए, आज हम देश के सामने खड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं, खास तौर पर बलूच विद्रोह, बीएलए से। लेकिन जातीयता पाकिस्तान में जातीयता क्रोध और उत्सुकता से भरी चीज़ है। राजनीतिक व्यवस्था में पंजाब का प्रभुत्व और सिंधियों या पश्तूनों या बलूचों की भावनाएं, मेरे कहने का मतलब है कि, वह खत्म नहीं हुई हैं। बात बस इतनी है कि सिंध में कोई मुखर आंदोलन नहीं है हालांकि मुझे लगता है कि सिंधु देश आंदोलन भी अब सामने आ रहा है। लेकिन बीएलए (BLA) एक गंभीर चुनौती है। यह एक गंभीर चुनौती है जिससे निपटने में मुझे लगता है कि सेना को भी समस्या आ रही है। सेना या राजनीतिक प्रतिष्ठान के साथ समस्या यह है कि उनके पास कोई दूसरा समाधान नहीं है। आप पाएंगे कि बातचीत के जरिए इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

वे केवल युद्ध की भाषा समझते हैं। अब, अफ़गानिस्तान में तालिबान के फिर से आने के बाद, पश्तून या ग्रेटर पश्तूनिस्तान का मुद्दा उठने वाला है। इस अर्थ में, पाकिस्तान की चिंताओं में से एक गुटनिरपेक्षता की मान्यता है, भले ही वे कहते हैं कि यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक औपचारिक सीमा है। तालिबान भी इसे मान्यता नहीं देता। पश्तून इसे स्वीकार नहीं करते या इसे मान्यता नहीं देते। इसलिए, उनके पास समस्याएं हैं। लेकिन सेना जिस तरह से इससे निपटने जा रही है, वह अनिवार्य रूप से बल का प्रयोग करके ही करेगी। क्योंकि अतीत में भी सेना ने शासन में अपनी भूमिका को यह कहकर उचित ठहराया है कि जब ये समस्याएं होंती हैं, तो उनसे निपटना सेना का ही काम है। मामले से निपटने का यही एकमात्र तरीका उन्हें समझ आता है।

इसलिए, हम शायद बीएलए द्वारा पैदा चुनौतियां अधिक देखेंगे क्योंकि बीएलए समस्या, टीटीपी समस्या सीपीईसी को भी जन्म देगी। सीपीईसी, जब तक सीपीईसी जारी रहेगा, मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें जो भी वित्तीय लाभ मिलते हैं, आर्थिक लाभ मिलते हैं, लेकिन बीएलए और टीटीपी चीन के कर्मचारियों, इंजीनियरों, बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते रहेंगे। बीएलए, मुझे नहीं लगता कि बीएलए के बलूचों को ग्वादर बंदरगाह स्वीकार्य होने जा रहा है। इसलिए, हम वास्तव में भविष्य में और अधिक समस्याओं के गवाह बनने जा रहे हैं।

अनिल त्रिगुणायत: धन्यवाद। जी हाँ, कृपया अपना सवाल पूछिए।

खबीबुल्लो मिर्ज़ोज़ोदा, काउंसलर, ताज़िकिस्तान दूतावास: जी। तो मेरा सवाल वास्तव में उन सभी से है जिन्होंने सुरक्षा और टीटीपी के भविष्य के बारे में जानकारी दी। जैसा कि हम जानते हैं, टीटीपी का रणनीतिक लक्ष्य पाकिस्तान में सत्ता में आना और अफ़गानिस्तान तालिबान की तरह शरिया शासन शुरू करना या लागू करना है। और उस लक्ष्य को पाने के लिए निश्चित रूप से, हम जानते हैं कि टीटीपी और काबुल तालिबान के बीच समझौता हुआ था कि वे पाकिस्तान में टीटीपी के रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे। अगर पाकिस्तान की भौगोलिक एकता पर संकट की बात हो रही है, तो क्यों? क्योंकि ख़ैबर पख़्तून अपनी स्वायत्तता का दावा कर रहे हैं और बलूच भी अपनी स्वायत्तत्ता का दावा कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, शायद समाज में विभाजन के कारण ये हमले या इस प्रकार के आंदोलन बढ़ जाएंगे। राजनीतिक दलों के कई सदस्य टीटीपी या अन्य समूहों के साथ मिलकर, फिर से व्यवस्था को बदलने और सरकार को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। आप इन प्रवृत्तियों और इस प्रकार के आंदोलन, जो सीमा पर और पाकिस्तान में, विशेष रूप से अफ़गानिस्तान के पड़ोसी राज्यों, गांवों में हो रहा है, के बारे में क्या सोचते हैं?

अजय दर्शन बेहरा: धन्यवाद। मैं इस प्रश्न का भी उत्तर दूंगा।

तान्या शर्मा: महादोय, मेरा नाम तान्या शर्मा है, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं सिविल- मिल्ट्री फ्यूज़न पर छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। पैनल में बैठे कोई भी सदस्य मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं, इसका क्या लाभ है... क्योंकि पाकिस्तान में परमाणु रिएक्टरों का निर्माण चीन की मदद से किया गया था। पाकिस्तान का पहले से ही संकट में होने की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? और वास्तव में परमाणु रिएक्टरों पर पाकिस्तान की मदद करना चीन के लिए किस प्रकार से राजनीतिक या आर्थिक रूप से लाभकारी है? धन्यवाद।

अनिल त्रिगुणायत: अंतिम सवाल। आप जाना चाहते हैं? आपका एक सवाल है?

शुभजीत रॉय: अगर संभव हो तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं इंडियन एक्सप्रेस से शुभजीत रॉय हूँ। मेरे पास सभी पैनलिस्टों से एक ही सवाल है जो अपने विचार साझा कर सकते हैं। पाकिस्तान में चल रहा संकट अंतर्दृष्टि से भरा हुआ है। मैं जानना चाहता था कि भारत को क्या करना चाहिए? और मैं चाहता हूँ कि आप सभी चार विकल्पों के बारे में सोचें। वार्ता करें; पूरी तरह से उदासीन हो जाएं; तीसरा विकल्प है उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाएं; और चौथा विकल्प है कि आग में घी डालने का काम करें। तो आपको क्या लगता है, भारत को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए?

अनिल त्रिगुणायत: बहुत अच्छे। आखिरी सवाल। जी हाँ, कृपया अपना प्रश्न पूछें। उन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया है।

आर्यन कपूर: धन्यवाद। नमस्कार। सर मेरा नाम आर्यन कपूर है। मैं सेंट स्टीफन कॉलेज से हूँ। मेरा सवाल बहुत साधारण है। इतिहास के पन्नों में हमेशा यह देखा गया है कि संकटों की बारहमासी श्रृंखला में आगे

चल कर विद्रोह और क्रांति की शक्ति भी जुड़ जाती। चीन के मामले में भी यही स्थिति है, संक्रमण काल में भी यही स्थिति है, जिस तरह से हमने इसके बारे में बात की है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान अभी बन्दूक की नली को देख रहा है और वह बारहमासी अवधि के संकटों की श्रृंखला का सामना कर रहे हैं जैसे कि तिलक सर ने बताया। इसलिए यदि वे निकट भविष्य में क्रांति या विद्रोह का सामना कर रहे हैं, जो वास्तव में पाकिस्तान देश के लिए एक बड़ा नरसंहार हो सकता है।

तिलक देवाशेर: आपके सवाल का जवाब बहुत लंबा है। मैं थोड़े शब्दों में उत्तर देने की कोशिश करूँगा। पाकिस्तान के निर्माण में बुनियादी संरचनात्मक दोष, बलूच और पश्तून बहुत पुराने हैं। उनकी अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति थी, इस्लाम के इस क्षेत्र में आने से बहुत पहले और निश्चित रूप से पाकिस्तान आने से बहुत पहले। अब, पाकिस्तान की समस्या यह थी कि आप इन ऐतिहासिक देशों को एक राष्ट्रीय पहचान में कैसे मिला सकते हैं? पहचान का सवाल जो पहले उठाया गया था।

उन्होंने सोचा कि वे धर्म का सहारा लेंगे। इस्लाम ही सीमा रेखा होगी क्योंकि वे सभी मुसलमान थे। दुर्भाग्य से, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जिन्ना से कहा था, अगर आपने उन्हें पढ़ा है या उनके बारे में सुना है, तो उन्होंने जिन्ना से कहा था कि वफ़ादारी कि इस्लाम में कहीं भी, कुरान में भी नहीं, धर्म या इस्लाम राष्ट्रवाद का आधार प्रदान करता है। किसी विशेष स्थान पर रहने वाले सभी लोग उसका हिस्सा बनते हैं। आप इस्लाम के आधार पर एक विशेष देश नहीं बना सकते। और उपमहाद्वीप में मुसलमानों की वफ़ादारी उनके संप्रदाय के प्रति है। पूरे इस्लाम के प्रति नहीं और ठीक यही हुआ है।

आज पाकिस्तान में सांप्रदायिकता इतनी गंभीर है। शिया- सुन्नी को, बरेलवी देवबंदी को काफ़िर समझते हैं। और तथ्य यह है कि बलूच ने पाकिस्तान की पहचान को स्वीकार नहीं किया है। वे खुद को पहले बलूच मानते हैं। इसी तरह, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पश्तून खुद को बलूच मानते हैं, क्योंकि उनका कोड एक जैसा है, पश्तून, बलूच की भाषा एक सी है, उनके रीति- रिवाज़ एक से हैं, वे आपस में विवाह

करते हैं। दो देशों में रहने के कारण वे राजनीतिक रूप से अलग- अलग विकसित हो सकते हैं, लेकिन वे अहमद शाह अब्दाली के समय से जुड़े हुए हैं, जब अफ़गानिस्तान अटक हुआ करता था और वे पंजाब थे।

इसलिए, इन संरचनात्मक मुद्दों के कारण पाकिस्तान में यह समस्या और भी गंभीर होती जा रही है जैसा कि आपने उल्लेख किया है। पाकिस्तान को इस समस्या से बहुत ही कल्पनाशील तरीके से निपटना होगा। दुर्भाग्य से, न तो पाकिस्तान में राजनीतिक वर्ग और न ही सेना, जो पंजाबी वर्चस्व वाली है, पंजाबी इसे समझ नहीं सकते। मैं पंजाबी हूँ। मुझे पता है। मैं ऐतिहासिक और प्राचीन जांच की बारीकियों को नहीं समझ सकता। समस्या बस यहीं है और आप पाएंगे कि यह और भी गंभीर होती जा रही है।

अनिल त्रिगुणायत: आखिरी वाला भी।

तिलक देवाशेर: ठीक है। वो था। हाँ, तो आपका सवाल था कि हमें मदद क्यों नहीं करनी चाहिए और आपने जो उल्लेख किया, कि आपने जो चार विकल्प दिए, मुझे वे आश्चर्यजनक लगे। आपको मदद क्यों करनी चाहिए? कोई व्यक्ति जो बीते 40 वर्षों से आप लोगों को मार रहा है, क्या आप उन्हें मदद करने की बजाए दुत्कारना पसंद नहीं करेंगे? आपको क्यों करना चाहिए? और आपको क्यों वार्ता करनी चाहिए? आपको समान शर्तों पर बात करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छुरी छुपा के रखता है और आतंकवाद को बढ़ावा देना जारी रखता है, आज खुल्लम- खुल्ला आतंकवाद चलाया जा रहा है बल्कि आपके पास ड्रोन हैं जो सीमा पर ड्रग्स, हथियार, जाली नोट गिराए जा रहे हैं।

फिर आपको उनसे बातचीत या उनकी तरफ मदद का हाथ क्यों बढ़ाना चाहिए? और आग में घी डालना, मुझे लगता है हमें भगवान नहीं बनना चाहिए। वे विस्फोट की स्थिति में हैं। हमें पानी और दूसरे मुद्दे पर बात करने का मौका नहीं मिला जो मेरे दिल के बहुत करीब है और आबादी के बारे में भी। वे फटने वाले हैं। भगवान मत बनिए। उन्हें सच में खुश रहने दीजिए, वे जो कर रहे हैं, उनके साथ चलिए। इसलिए हमें

न तो आग में घी डालना चाहिए, न ही उनसे उलझना चाहिए और न ही उनकी मदद करनी चाहिए। उदासीनता, हाँ। यही है जो हम कर रहे हैं।

शालिनी चावला: मुझे लगता है कि सवाल चीन के बारे में था, जिसके बारे में आपने पूछा कि चीन क्यों मदद कर रहा है। चीन की दिलचस्पी 60 के दशक से ही भारत का मुकाबला करने में रही है। चीन ने वास्तव में 1960 के दशक में ही पाकिस्तान को परमाणु बम देने की पेशकश की थी और अयूब खान ने यह कहते हुए उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था कि पाकिस्तान इतना खर्चा नहीं उठा सकता। भुट्टो उस समय कैबिनेट में थे और वे इस बात से बहुत परेशान हुए थे। साल 1971 में सत्ता में आते ही भुट्टो ने इस अवसर का लाभ उठाया और पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया।

इसलिए चीन के लिए पाकिस्तान एक बहुत ही सस्ता विकल्प है, भारत का मुकाबला करने के लिए किफायती विकल्प। भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन की साझा दुश्मनी उनके लिए एक बंधन रही है और यह बदलने वाला नहीं है। ज़ाहिर है कि चीन की तेल की तलाश के संदर्भ में उनके रणनीतिक गठबंधन के अन्य विकल्प, पहलू भी थे, जिसे वह अब हासिल करने में कामयाब रहा है और वह ग्वादर का प्रबंधन देख रहा है। इसलिए दीर्घकाल में उसके पास तेल मार्गों को नियंत्रित करने की क्षमता होगी, शायद ऐसा हो सकता है। यह पाकिस्तान को इस क्षेत्र के लिए एक संयोजक के रूप में भी देखता है जहाँ वह अपना आधार बना सकता है और हमने देखा है कि उसने किस तरह से विस्तार किया है, उसने ईरान, अफ़गानिस्तान, अन्य पहलुओं में अपना स्थान बनाया है।

लेकिन इस गठबंधन में भारत विरोधी पहलू सबसे मजबूत पहलू है। और यही कारण है कि पाकिस्तान को परमाणु हथियार संपन्न देश बनाना चीन के उद्देश्यों में मददगार रहा है। चीन के पास खुद पहले इस्तेमाल न करने का सिद्धांत है, लेकिन उसने पाकिस्तान के पहले इस्तेमाल के सिद्धांत पर कभी सवाल नहीं उठाया और यह तथ्य भी है कि पाकिस्तान ने इसे वैसे ही रखा है, यह सिर्फ अपारदर्शी रहा है, इसके पास

कोई लिखित सिद्धांत नहीं है और वह अक्सर परमाणु हमले की धमकी का सहारा लेता है। इसलिए आपने कभी इस पर सवाल उठते नहीं देखा और आपने देखा है कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट के बावजूद इसे बरकार रखा गया है।

कुल मिलाकर पाकिस्तान आर्थिक संकट के इस बड़े दौर से गुज़रा है लेकिन आधुनिकीकरण और परमाणु निर्माण निरंतर बना हुआ है। यह बदलने वाला नहीं है, भले ही वहां चीन के कर्मचारियों की हत्या की जा रही हो। एक और सवाल था और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सवाल था। मैं श्री देवाशेर से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें इस बात में उलझने की जरूरत नहीं है कि भारत के पास क्या विकल्प हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम केवल अपने विकास, अपने आर्थिक विकास, सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करें, और बहुत महत्वपूर्ण संकेत दें कि हम आतंकवाद के लिए पूर्ण असहनशीलता (ज़ीरो टॉलरेंस) रखते हैं।

मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए भी यही जारी रहना चाहिए। एक बार जब पाकिस्तान अपने होशों-हवास में आ जाएगा, वह अपनी राह बदलने का फैसला कर लेगा तो भारत शायद किसी तरह की सशर्त भागीदारी के बारे में विचार कर सकता है।

अनिल त्रिगुणायत: धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में क्रांति होगी?

तिलक देवाशेर: मैंने इस बारे में विचार नहीं किया है लेकिन मुझे लगता है कि क्रांति की एक समस्या यह है कि लोकतंत्र में क्रांति आसानी से नहीं होती। और वास्तव में आपके कहने का अर्थ यह है कि क्या व्यवस्था में कोई बदलाव होगा? मेरा मतलब है, आप व्यवस्था के भीतर बदलाव ला सकते हैं तो आप इसे व्यवस्था के भीतर एक परिवर्तनकारी बदलाव के रूप में देख सकते हैं लेकिन यह कोई ऐसी क्रांति नहीं होगी जो व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगी।

क्रांति की एकमात्र संभावना पाकिस्तान में इस्लामी क्रांति ही है। मेरे कहने का अर्थ है हमें उस संभावना को बिल्कुल भी खारिज़ नहीं करना चाहिए यानि भले ही सेना इसके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन दीर्धकाल में हमारे लिए इस समय यह कहना मुश्किल है कि भविष्य में पाकिस्तान इस्लामवादियों के हाथों में होगा। हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। लेकिन इस सवाल पर, मेरा ...

अनिल त्रिगुणायत: चाल विकल्पों पर।

अजय दर्शन बेहरा: चार विकल्प, जी हाँ। इन पर मेरा अलग नज़रिया है और मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान के साथ वार्ता करनी चाहिए। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हमारे संबंध केवल देश के साथ नहीं है। हमारे संबंध पाकिस्तान के लोगों के साथ बी है। मेरे कहने का अर्थ है कि समस्या भविष्य में कभी- न- कभी तो होगी, हम ऐसी स्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ हमें बांग्लादेश के साथ होने वाली समस्या का सामना करना पड़ेगा। संबंधों में सुधार होने पर पाकिस्तान के साथ भी हमें ठीक वैसी ही समस्याओं से दो- चार होना पड़ेगा। इसलिए यह सत्ता में मौजूद शासन का सवाल नहीं है।

हमें यह देखना होगा कि लोग भारत को किस तरह से देखते हैं और पाकिस्तान के प्रति भारत की उदासीनता कैसी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि संबंध बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं होगें। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप उनसे आतंकवाद के मुद्दे पर लगातार बात करते रहें। आपके पास कुछ हद तक व्यापारिक संबंध भी है जो आर्थिक रूप से पंजाब को लाभ पहुँचाने वाला है। आर्थिक रूप से यह व्यापारियों को लाभ पहुँचाने वाला है और यह सीमा के आस-पास के कुछ इलाकों के लिए आर्थिक परिवर्तन लाने वाला है। जिससे दूसरे देश के बारे में लोगों की धारणा में बहुत अंतर आएगा।

तो, अभी, मेरा मतलब है पाकिस्तान के लोगों की धारणा, मैं देश या सेना के बारे में चिंतित नहीं हूँ। पाकिस्तान के लोगों की धारणा भारत के बारे में बहुत नकारात्मक है। आप इसे आसानी से जान सकते हैं, आप वहां के अख़बारों को देखें और पाएंगे कि भारत देश के बारे में किस तरह की ख़बरें वहां चल रही हैं। यह तभी बदल सकता है जब हम उनके साथ बातचीत करें।

अनिल त्रिगुणायत: बहुत- बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात है, मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने देखा होगा और जो लोग पाकिस्तान के प्रेस पर नज़र रखते हैं। मीडिया और दूसरे माध्यमों से भी जो टिप्पणियां आ रही हैं, उनमें भारत की प्रगति के बारे में बात की जा रही है और आपने यह भी देखा होगा कि वे बहुत ही बे-मन से प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। इसलिए, पाकिस्तान में निश्चित रूप से यह अहसास हो रहा है कि भारतीय मॉडल सफल रहा है और यह एक तरह से अच्छी बात है। इसका अपना अलग प्रभाव है।

हमने पैनल में शामिल बहुत विद्वान सदस्यों को सुना, इन्होंने पाकिस्तान के मौज़ूदा हालात और यह किस तरह अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ेगा, इस बारे में चर्चा की। मैं इस संबंध में भारत की नीति को दोहरा सकता हूँ। वह यह है कि हम पाकिस्तान के लोगों की समृद्धि चाहते हैं। उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा आपने इस्लामी क्रांति का उल्लेख किया है, वैसा ही हो। आपको नहीं पता कि उस मामले में किस रास्ते पर जाना है।

बांग्लादेश आपके लिए एक और उदाहरण है। क्रांतियां भी हमेशा लोगों के लिए आसान नहीं होती हैं। मैं मूल रूप से मध्य पूर्व के मामलों का विशेषज्ञ हूँ। यह अभी भी बहुत मुश्किल दौर में है। मैंने शुरूआत की है, इसे बाहर से इंजीनियर किया गया था। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में दशकों से क्या हुआ है। इसलिए, आपको वास्तव में इसे अलग- अलग नज़रियों से देखना होगा।

इसलिए, आखिर में मैं पैनल के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा और शुभजीत, आपके प्रश्न के बारे में मेरा विचार था और मैं एक पूर्व राजनयिक के रूप में कह रहा हूँ कि हम हाइब्रिड तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम सीधे- सीधे द्विपक्षीय वार्ता नहीं कर सकते हैं। हम अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, कैदियों की सूची, करतारपुर कॉरिडोर का आदान- प्रदान करते हैं। हम शंघाई सहयोग संगठन में भी उनके साथ मिलकर काम करते हैं। अन्य क्षेत्रों में, वे ब्रिक्स में हो सकते हैं, हम उनके साथ काम करेंगे। डॉ. जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। एससीओ आरएटीएस बुनियादी ढांचे में, हम एक साथ काम करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में जब भी कोई समस्या आती है, हम साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आधिकारिक तौर पर हमारे बीच संवाद/बातचीत नहीं हो सकती, यह हमारा अतीत है। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम पाकिस्तान की ओर न देखें। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान हमारी मुख्य चुनौती हुआ करता था। आज हमारी मुख्य चुनौती चीन है, पाकिस्तान नहीं। लेकिन चीन और पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सब का धन्यवाद।

ध्रुबज्योति भट्टाचार्य: धन्यवाद। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज परिषद की ओर से हम सभी ने एक आकर्षक और ज्ञान समृद्ध पैनल चर्चा का आनंद लिया। मैं प्रतिष्ठित अध्यक्ष और पैनल के सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे सभी श्रोताओं को मेरा विशेष धन्यवाद। आईसीडब्ल्यूए के शोध कार्य, आयोजनों, आउटरीच कार्यक्रमों और प्रकाशनों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट देखें या हमारे ट्विटर या एक्स (X), लिंक्डइन (LinkedIn), यू- ट्यूब (YouTube) और फेसबुक हैंडल पर जाएं। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद और कृपया उप- कक्ष में हमारे साथ चाय का आनंद लें। धन्यवाद।